राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 15 सितम्बर, 2009 / 24 भाद्रपद, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

योजना विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी)

अधिसूचना

31 अगस्त, 2009

संख्या पी0एल0जी0–ए(3)–5 / 2007(निजी सचिव).––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में निजी सचिव, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न ''उपाबंध–क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, निजी सचिव, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

उपाबन्ध ''क''

हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में निजी सचिव, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.––**निजी सचिव

2. **पदों की संख्या.––**01 (एक)

3. **वर्गीकरण.––**वर्ग–I (राजपत्रित)

4. **वेतनमान.––**7220–220–8100–275–10300–340–11660 रूपये ।
; (विस्तृत रूप में अंकित करें)।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.––**अचयन ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.––**लागू नहीं।

7. **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––** लागू नहीं।

8. **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.––आयु.––**लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं.––लागू नहीं।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––**दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. **भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––**शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सेकेण्डमेंट आधार पर ।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.––** निजी सहायक में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका ग्रेड में 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। ऐसा न होने पर वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से जिनका ग्रेड में 11 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 11 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। ऐसा न होने पर वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से, प्रोन्नति द्वारा जिनका वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संयुक्त रूप में 16 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल हो जिसके अंतर्गत 4 वर्ष का सेवाकाल वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप

में अनिवार्य होगा ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सेकेंडमेन्ट द्वारा।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी;

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवाए जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने संबंधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तुक के अंतर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्म्ड फोर्सिस परसोनेल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अंतर्गत भर्ती किया गया है और इनके अंतर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अंर्तगत भर्ती किया गया हो और इनके अंर्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––जैसी कि सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––लागू नहीं।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन–जातियों / पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए अनुदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997, में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शाक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेशों द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी।

———————

[*Authoritative English text of Government Notification No.PLG-A*(3)-5/2007 *(Private Secretary) Dated* 31-8-2009*, as required under clause*(3) *of Article* 348 *of the constitution of India*].

PLANNING DEPARTMENT
(Economics & Statistics)

NOTIFICATION

the 31st *August,* 2009

No. PLG-A(3)-5/2007(Private Secretary).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Private Secretary, Class-I, (Gazetted) in the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh, as per "Annexure-A" attached to this notification, namely:—

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh, Private Secretary, Class-I, (Gazetted) Recruitment and Promotion rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

———————

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PRIVATE SECRETARY, CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the post.—**Private Secretary

2. **Number of posts.—**01 (One)

3. **Classification.—**Class-I (Gazetted)

4. **Scale of pay.—** Rs.7220-220-8100-275-10300-340-11660
(Be given in expanded notation).

5. Whether Selection post or nonselection posts.—Non Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable.

7. Minimum Educational & other qualifications required for direct recruits.—Not applicable.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.—Age.—Not applicable.

Education Qualification.—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Personal Assistant who possesses 5 years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service rendered, if any in the grade failing which from amongst the Senior Scale Stenographers, having eleven years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service rendered, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Senior Scale Stenographers having sixteen years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service combined as Senior Scale Stenographer and Junior Scale Stenographers which shall include 4 years essential service as Senior Scale Stenographer failing which on secondment from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale in other Himachal Pradesh Government Departments.

(1) In all cases of promotion, the continuous ad-hoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;

In all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 03 years or that prescribed in the R&P Rules for the post whichever is less.

Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited

under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services), 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous *adhoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that *inter-se*-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a directrecruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

———————

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–4, 26 अगस्त, 2009

संख्या वि0 स0–लैज–गवरनमैंट बिल / 1–39 / 2009.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 21) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2009 को हिमाचल

प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थपित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(गोवर्धन सिंह),
सचिव।

————————

2009 का विधेयक संख्यांक 21

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.––**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2009 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.––**मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

''(क)	मुख्य मन्त्री	चौंतीस हजार रुपए प्रतिमास;
(ख)	कैबिनेट मन्त्री	इकतीस हजार रुपए प्रतिमास;
(ग)	राज्य मन्त्री	अट्ठाईस हजार रुपए प्रतिमास; और
(घ)	उप मन्त्री	सत्ताईस हजार रुपए प्रतिमास।''।

3. **धारा 10 का संशोधन**.––मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''सात हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 3 के अधिनियमित किये जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 27.36 लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

————————

प्रत्यायोजित विधान समबन्धी ज्ञापन

–शून्य–

————————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[जी0ए0डी0 फाईल नं0 जी0ए0डी0–सी(डी)6–1 / 2004]

हिमाचल प्रदेश की राज्पाल, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2009 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 2007 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिशे करती हैं।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और यथेष्ठ खर्चों, जो कि माननीय मन्त्रियों, जन प्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनके विद्यमान वेतन और दूरभाष भत्ते को बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। इसलिए मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मंत्री।

शिमला.....
दिनांक..... अगस्त, 2009

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 21 of 2009

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2009

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2009.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (11 of 2000) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for clauses (a) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(a)	**Chief Minister**	**Rupees thirty four thousand per mensem;**
(b)	**Cabinet Minister**	**Rupees thirty one thousand per mensem;**
(c)	**Minister of State**	**Rupees twenty eight thousand per mensem; and**
(d)	**Deputy Minister**	**Rupees twenty seven thousand per mensem.".**

3. Amendment of section 10.—In section 10 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso, for the words "**seven thousand rupees",** the words **"ten thousand rupees"** shall be subsitituted.

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which an Hon'ble Ministers, as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase their existing salaries and telephone allowance. This has neccessitated the amendments in the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Shimla :

The……August, 2009.

———

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 and 3 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 27.36 lakhs per annum approximately.

———

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSITUTION OF INDIA
[GAD File No. GAD-C(D)-(6)-1/2004]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 2009, recommends, under article 207 of the Consitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

Sections to be effected due to the proposed amendments in The Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

3. Salaries and allowances.—(1) Each Minister shall be entitled to receive a salary at the following rates, namely :—

(a)	Chief Minister	Eighteen thousand rupees per mensem;
(b)	Cabinet Minister	Fifteen thousand rupees per mensem;
(c)	Minister of State	Eleven thousand rupees per mensem; and
(d)	Deputy Minister	Ten thousand rupees per mensem.

(2) Each Minister shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.

(3) Each Minister shall be entitled to receive an allowance for each day during the whole of his term at the same rate as specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

Section 10. Free installation of telephone.—(1) Each Minister shall be entitled to have a telephone installed at any place within his constituency or at his permanent place of residence, if such facility is available at such place at normal rates and without incurring any additional cost, as may be specified by him, and after the place of installation is so specified, the charges for first installation of security deposit and annual rent for, such telephone shall be borne by the State Government and all other expenses such as those relating to, local and outside calls shall be paid by the Minister:

Provided that the expenditure on local and outside calls incurred by a Minister in any month shall be reimbursed by the Government subject to a maximum of (seven thousand) rupees:

Provided further that a Minister may continue to avail himself of the facility of telephone provided to him for a period not exceeding 15 days from the date of his ceasing to be a Minister.

(2) All expenses which are payable by a Minister in relation to the telephone installed under sub-section (1) shall be paid by him directly in cash and if it is not so done, the same may be adjusted by the State Government against any amount due to him from the State Government.

———————

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला, 26 अगस्त, 2009

संख्या वि0स0–लैज–गवरनमैंट बिल / 1–38 / 2009.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 22) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(गोवर्धन सिंह),
सचिव।

———————

2009 का विधेयक संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

2. **धारा 3 का संशोधन .**––हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4), (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द ''पन्द्रह हजार रुपए'' के स्थान पर ''इकतीस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

3. **धारा 4 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में ''ग्यारह हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''अट्ठाईस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

4. **धारा 8 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''सात हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ठ खर्चों, जोकि माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जन प्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनके विद्यमान वेतन और दूरभाष भत्ते को बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 में संशोधन किया जाना आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला .....

तारीख ..... अगस्त, 2009

————————

वित्तीय ज्ञापन

विधयेक के खण्ड 2, 3 और 4 के अधिनियमित किये जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 4.68 लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[जी0ए0डी0 फाईल नं0 जी0ए0डी0–सी (डी) 6–1 / 2006]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2009 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

————————

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वोल हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) के उपबन्धों के उद्धरण।

अध्यक्ष का वेतन आदि.––(1) अध्यक्ष प्रतिमाह पन्द्रह हजार रुपये की दर से वेतन और अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(1–अ) अध्यक्ष प्रतिमास पांच हजार रुपये की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) अध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा शिमला में निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार उसे उसके अध्यक्ष न रहने

की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि तक गृह का निःशुल्क अधिभोगी बने रहने की अनुज्ञा भी दे सकेगी।

'उपाध्यक्ष का वेतन आदि.—— (1) उपाध्यक्ष प्रतिमाह ग्यारह हजार रुपये की दर से वेतन और अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान, प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर, भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(1–अ) उपाध्यक्ष प्रतिमास पांच हजार रुपये की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) उपाध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा शिमला में निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार वहन करेगी या उसके बदले में उसे तीन सौ रुपये प्रतिमाह से अनधिक ऐसा भत्ता जो राज्य सरकार नियत करे, सन्दत्त किया जाएगा। राज्य सरकार उसे उसके उपाध्यक्ष न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि तक गृह का निःशुल्क अधिभोगी बने रहने की अनुज्ञा भी दे सकेगी।

स्पष्टीकरण.——उपाध्यक्ष किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा, यदि उसका निवास के लिए आबंटित गृह का मानक किराया एक सौ पच्चास रुपये से अधिक हो जाता है।

8. टैलीफोन की निःशुल्क स्थापना.——(1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रत्येक, अपने निर्वाचन के भीतर किसी स्थान पर या अपने स्थायी निवास स्थान पर जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे एक टैलीफोन स्थापित कराने का, यदि ऐसे स्थान पर, ऐसी सुविधा साधारण दरों और कोई अतिरिक्त उपगत किए बिना उपलब्ध है, हकदार होगा, और स्थापना के स्थान को इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाने के पश्चात् ऐसे टैलीफोन की प्रथम स्थापना का प्रचार, प्रतिभूति निक्षेप और वार्षिक किराया राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और अन्य जैसे कि स्थानीय या वाह्य कालों से सम्बन्धित व्यय यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संदत्त किए जाएंगेः

परन्तु यह कि यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जो इस उप–धारा के अधीन टैलीफोन (दूरभाष) स्थापित करता है, सात हजार रुपये प्रतिमास टैलीफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उन्हें प्रदान की गई टैलीफोन सुविधा का उपयोग उनके, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रहने की तारीख से अधिक से अधिक पन्द्रह दिन तक की अवधि तक करते रह सकेंगे।

(2) ऐसे सभी व्यय, जो उप–धारा (1) के अधीन स्थापित टैलीफोन के सम्बन्ध में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा देय है, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा सीधे नकद रूप से संदत्त किए जाएंगे और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, को शोधय किसी राशि के विरुद्ध राज्य सरकार के द्वारा समायोजित किया जा सकेगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 22 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 2009

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries, Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows.—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2009.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1971) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the words "fifteen thousand rupees", the words "thirty one thousand rupees" shall be substituted.

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "eleven thousand rupees", the words "twenty eight thousand rupees" shall be substituted.

4. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso, for the words "seven thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which Hon'ble Speaker and Deputy Speaker, as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase their existing salaries and telephone allowance. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Shimla :
The ..... August, 2009

———————

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2, 3 and 4 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 4.68 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C(D)(6)-1/2006]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salarties (Amendment) Bill, 2009, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

Sections to be effected due to the proposed amendments in the Himachal Pradesh Legislative assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

3. Salary etc. of the Speaker.—(1) The Speaker shall be entitled to receive a salary at the rate of fifteen thousand rupees per mensem and an allowance for each day during the whole of his term at the same rates as are specifed in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

(1-A) The Speaker shall be entitled ro receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem].

(2) The Speaker during the term of his office shall be provided by the State Government, a free furnished house at Shimla, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government may also all him to continue in free occupation of the house for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be the Speaker.

[1][3-A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

4. Salary etc. of the Deputy Speaker.—(1) The Deputy Speaker shall be entitled to receive a salary at the rate of eleven thousand rupees per mensem and an allowance for each day during the whole of his term at the same rates as are specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

(1-A) The Deputy Speaker shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem].

(2) The Deputy Speaker during the term of his office shall be provided by the State Government, a free furnished house at Shimla, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government or in lieu thereof he shall be paid such allowance not exceeding three

hundred rupees per mensem as the State Government may fix. The State Government may also allow him to continue in free occupation of the house for period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be the Deputy Speaker.

Explanation.—The Deputy Speaker shall not become liable personally for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds one hundred and fifty rupees per mensem.

8. Free installation of the telephone.—(1) The Speaker and the Deputy Speaker shall each be entitled to have a telephone installed at any place within his constituency or at his permanent place of residence, if such facility is available at such place at normal rates and without incurring any additional cost, as may be specified by him and after the place of installation is so specified, the charges of first installation of, security deposit and annual rent for, such telephone shall be borne by the State Government and all other expenses such as those relating to local and outside calls shall be paid by the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be :

Provided that the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, who installs a telephone uder this sub-section shall be paid a telephone allowance at the rate of seven thousand rupees per mensem.] :

Provided further that the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, may continue to avail himself of the facility of telephone provided to him for a period not exceeding 15 days from the date of his ceasig to be the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be].

(2) All expenses which are payable by the Speaker or the Deputy Speaker in relation to the telephone installed under sub-section (1) shall be paid by the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, directly in cash and if it is not so done, the same may be adjusted by the State Government against any amount due to the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, from the State Government.

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–4, 26 अगस्त, 2009

संख्या वि0स0–लैज–गवरनमैंट बिल / 1–40 / 2009.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 24) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(गोवर्धन सिंह),
सचिव।

2009 का विधेयक संख्यांक 24

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमत हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2009 है ।

2. **धारा 3 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उप–धारा (1) में ''आठ हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''पन्द्रह हजार रुपये'' शब्द रखे जाएंगे ।

3. **धारा 4–ख का प्रतिस्थापन.––**मूल अधिनियम की धारा 4–ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :––

> ''**4–ख निर्वाचन क्षेत्र भत्ता.––**प्रत्येक सदस्य को बीस हजार रुपये की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्रतिमास संदत्त किया जाएगा ।''।

4. **धारा 4–खख का प्रतिस्थापन.––**मूल अधिनियम की धारा 4–खख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :––

> ''**4–खख कार्यालय भत्ता.––**प्रत्येक सदस्य को पांच हजार रुपये प्रतिमास की दर से कार्यालय भत्ता संदत्त किया जाएगा ।''।

5. **धारा 5 का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक में ''सात हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे ।

6. **धारा 6–क.क. का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 6–कक में ''सचिवीय डाक सुविधाओं और'' तथा ''सचिवीय, डाक सुविधाएं'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

7. **धारा 6–ख का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 6–ख में,––

> (क) उपधारा (1) में ''पांच हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रुपये'' शब्द रखे जाएंगे; और
>
> (ख) खण्ड (ङ) के प्रथम परन्तुक में ''दो सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''चार सौ रुपये'' शब्द रखे जाएंगे ।''।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ठ खर्चों, जो राज्य विधान सभा के माननीय सदस्यों का जनप्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनकी विद्यमान

उपलब्धियों सुख–सुविधाओं में संशोधन की लगातार मांग रही है। इसलिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मंत्री।

शिमला.....
दिनांक.....अगस्त, 2009.

———————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 7 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 120 लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

———————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[जी0ए0डी0 फाईल नं0 जी0ए0डी0–सी (डी) 6–1 / 2007]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2009 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

———————

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश विधान सभा के (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) के उपबन्धों के उद्धरण

3. वेतन और प्रतिकरात्मक भत्ता.––इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य को इस अधिनियम के प्रदत्त होने की तारीख से या उसके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से या यदि ऐसी घोषणा रिक्ति होने से पहले की गई हो, तो रिक्ति होने की तारीख से, इन दोनों में से जो भी बाद में हो, प्रति मास आठ हजार रुपये की दर से वेतन और पांच हजार रुपये की दर से प्रतिकरात्मक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(2) X X X X
(3) X X X X

(4) इसमें इससे पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सदस्य को किसी ऐसी अवधि के, बारे में, जिसके दौरान यह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिक निरोध में या, कोई वेतन और प्रतिकरात्मक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.––इस प्रयोजन के लिए विधिक निरोध के अन्तर्गत किसी निवारक निरोध से सम्बन्धित विधि के अधीन निरोध नहीं है।

4–खख. कार्यालय भत्ता और चालक भत्ता.––प्रत्येक सदस्य को पांच हजार रुपये प्रतिमास की दर से कार्यालय भत्ता और चार हजार रुपये प्रतिमास की दर से चालक भत्ता दिया जाएगा।''।

5. सुख सुविधाएं.––(1) सदस्य, सभा की बैठक के स्थान पर, रियायती दरों पर ऐसे निवास स्थान का हकदार होगा जो धारा 7 के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाए।

(2) प्रत्येक सदस्य एक टैलीफोन अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी स्थान पर या अपने स्थायी निवास के स्थान पर, यदि ऐसे स्थान पर ऐसी सुविधा साधारण दरों पर और कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना उपलब्ध है, या शिमला में, जैसा भी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए संस्थापित कराने का हकदार होगा और संस्थापन के स्थान के ऐसे विनिर्दिष्ट किए जाने के पश्चात् ऐसे टैलीफोन के प्रथम संस्थापन के लिए प्रभार और प्रतिभूति–निक्षेप और वार्षिक किराया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और अन्य सभी व्यय, वे जो कि स्थानीय या वाह्य कालों से सम्बन्धित हैं, सदस्य द्वारा संदत्त किए जाएंगे :

परन्तु ऐसे सदस्यों को, जो इस उप–धारा के अधीन टैलीफोन संस्थापित कराएगा प्रतिमास सात हजार रुपए की दर से टैलीफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई सदस्य उसके निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी स्थान पर या उसके स्थाई निवास स्थान पर या शिमला में टैलीफोन संस्थापित नहीं करता है, तो उसे प्रतिमास दो सौ रुपये की दर से टैलीफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा।

6–कक, वेतन और प्रतिकरात्मक, निर्वाचन क्षेत्रीय, सचिवीय, डाक सुविधाओं और टैलीफोन भत्तों और अन्य परिलब्धियों का आय कर से अपवर्जित होना.––इस अधिनियम के अधीन सदस्य की संदेय वेतन और प्रतिकरात्मक, निर्वाचन क्षेत्रीय, सचिवीय, डाक सुविधाएं और टैलीफोन भत्ता और उसे अनुज्ञेय परिलब्धियां आय कर से अपवर्जित होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संदेय होगा।

स्पष्टीकरण.––राज्य द्वारा संदेय आय कर की रकम आय कर के लिए निर्धारित आय की प्रथम स्लैब होगी, अर्थात् इस रकम के निर्धारण में सम्बन्धित सदस्य की आय के अन्य स्रातों को गिनती में नहीं लिया जाएगा।

6–ख––

(1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने––

(क) विधान सभा के सदस्य, या

(ख) श्रेत्रीय परिषद् सदस्य, या

(ग) भागतः विधान सभा के सदस्य और भगतः क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य, या

(घ) (1) पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के तत्कालीन राज्य की विधान सभा; या

(2) तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा, या

(3) तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान परिषद्; या

(4) भागतः एक और भागतः दूसरी के सदस्य जिन्हें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए पूर्ण क्षेत्र या उसके भाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया है,

(ङ) भागतः विधान सभा के सदस्य और भागतः यथास्थिति, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य क्षेत्र के तत्कालीन राज्य या तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में पांच वर्ष तक किसी अवधि के लिए सेवा की है, प्रतिमास पांच हजार रुपए पेन्शन संदत्त की जाएगी :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने पांच वर्ष से अधिक अवधि तक उपयुक्त रूप से सेवा की है, वह उसे प्रत्येक वर्ष के प्रतिमास दो सौ रुपए की अतिरिक्त पेन्शन संदत्त की जाएगी, किन्तु वर्ष के भाग को एक वर्ष के रूप में संगणित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक के अधीन संदेय अतिरिक्त पेन्शन के अवधारण करने के लिए अवधि की संगणना करते समय, हिमवाधित क्षेत्र (असमरूप क्षेत्र) में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की दशा में, जहां निर्वाचन आम चुनाव के लिए नियत दिन के पश्चात्वर्ती किसी भी दिन करवाए जाते हैं या करवाए जा सकेंगे, उस तारीख, जिसको आम चुनाव में विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और वह तारीख जिसको, हिमवाधित (असमरूप क्षेत्र) से निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, की मध्यवर्ती अवधि की भी गणना की जाएगी।

स्पष्टीकरण.––पद ''हिमवाधित क्षेत्र (असमरूप क्षेत्र)'' से किन्नौर और लाहौल एवं स्पिती जिले तथा चम्बा जिला में तहसील पांगी और भरमौर अभिप्रेत हैं।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन का हकदार कोई व्यक्ति––

(i) राष्ट्रपति या उप–राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाता है; या

(ii) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (1966 का 19) की धारा (3) के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य बन जाता है; या

(iii) वेतन पर केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम में या स्थानीय प्राधिकरण में नियोजित या राज्य सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकरण से अन्यथा कोई पारिश्रमिक पाने का हकदर हो जाता है ;

तो ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए जिसके वह ऐसा पद धारण किए रहता है या ऐसा सदस्य बना रहता है, या ऐसे नियोजित है या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहता है, उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन पाने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति ऐसे पद धारण करने या ऐसा सदस्य रहने या ऐसे नियोजित रहने के लिए संदेय वेतन या जहां ऐसे व्यक्ति को संदेय खण्ड (iii) में निर्दिष्ट पारिश्रमिक किसी भी दशा में उप–धारा (1) के अधीन उस संदेय पेन्शन से कम है, वह ऐसा व्यक्ति उस उप–धारा के अधीन पेन्शन के रूप में केवल अतिशेष को प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) जहां उप धारा (1) के अधीन पेन्शन पाने का हकदार कोई व्यक्ति कोई अन्य पेन्शन पाने का भी हकदार है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी अन्य पेन्शन के साथ–साथ उप–धारा (1) के अधीन, पेन्शन प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणना करने में उस अवधि की भी गणना की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) में यथा परिभाषित मंत्री के रूप में या विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संघ राज्य क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा की है।

(5) जहां उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन या पेन्शन लेने के हकदार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो:––

(i) उसकी पत्नी / पति अपने जीवन काल में या पुनर्विवाह पर्यन्त; या
(ii) यदि ऐसे व्यक्ति की पत्नी / पति नहीं है तो व्यस्कता की आयु अभिप्राप्त करने पर्यन्त, उसकी सन्तान और पुत्रियों की दयाा में उनके विवाह पर्यन्त, अनुज्ञेय पेन्शन के 50 प्रतिशत की दर पर पेन्शन लेने के हकदार होंगे :

परन्तु जहां इस उप–धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेन्शन लेने के हकदार हों तो ऐसे सभी व्यक्ति उक्त पेन्शन को समान अंश में लेने के हकदार होंगे।

(5–अ) इस धारा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (1–अ) के अधीन पेंशन लेने का हकदार हो गया होता, किन्तु फरवरी, 1989 के सातवें दिन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह ऐसी पेन्शन नहीं ले सका वहां उसकी पत्नी, पति, अवयस्क संतान या अविवाहित पुत्रियों उप–धारा (5) के अधीन पेंशन लेने का हकदार होंगे, मानों कि ऐसा व्यक्ति फरवरी, 1989 के सातवें दिन को जीवित था।

(6) इस धारा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन लेने का हकदार हो गया होता, किन्तु दिसम्बर, 1976 के इक्तीसवें दिन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह ऐसी पेन्शन नहीं ले सका, तो––

(*i*) उसके जीवन काल में या उसके पुनः विवाह करने पर्यन्त उसका पति / पत्नी, या

(*ii*) यदि ऐसे व्यक्ति का पति / पत्नी नहीं है तो उसकी अवयस्क सन्तान व्यस्कता की आयु प्राप्त करने के पर्यन्त और पुत्रियों की दशा में उनके विवाह करने पर्यन्त,

उस राशि के बराबर पेन्शन जो ऐसे व्यक्ति ने पेन्शन के रूप में प्राप्त की होती, यदि वह दिसम्बर, 1976 के इकतीसवें दिन को जीवित होता या तीन सौ पचहतर रुपये की राशि प्रति मास, इन दोनों में से जो अधिक हो, लेने का हकदार होगा / होगी :

परन्तु इस उप–धारा के अधीन तीन सौ पचहतर रुपये की उच्चतर सीमा जनवरी, 1986 के चौबीसवें दिन से मार्च, 1988 के इक्तीसवें दिन तक की कालावधि की पेन्शन के लिए लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां उप–धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेन्शन के हकदार हों तो ऐसी सभी व्यक्ति उक्त पेन्शन को बराबर हिस्सों में लेंगे।

(7) प्रत्येक व्यक्ति को जो इस धारा के अधीन पेन्शन / कुटुम्ब पेंशन लेता है या पेंशन / कुटुम्ब पेंशन लेने का हकदार है, अनुज्ञेय पेन्शन / कुटुम्ब पेंशन के अतिरिक्त, उसी दर से पेन्शन पर महंगाई राहत संदत्त की जाएगी जो राज्य सरकार के अन्य पेन्शन भोगियों को अनुज्ञेय है।

———

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 24 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2009

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follow :—

1. *Short title.*—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2009.

2. *Amendment of section 3.*—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (8 of 1971) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the words **"eight thousand rupees",** the words **"fifteen thousand rupees"** shall be substituted.

3. *Substitution of section 4-B.*—For section 4-B of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"4-B. Constituency allowance.—There shall be paid to each member a constituency allowance at the rate of twenty thousand rupees per mensem.".

4. *Substitution of section 4-BB.*—For section 4-BB of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"4-BB. Office Allowance.—There shall be paid to each Member an office allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.".

5. *Amendment of section 5.*—In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), in first proviso, for the words **"seven thousand rupees"**, the words **"ten thousand rupees"** shall be substituted.

6. *Amendment of section 6-AA.*—In section 6-AA of the principal Act, the words and sign "secretarial, postal facilities and" and "secretarial, postal facilities" shall be omitted.

7. *Amendment of section 6-B.*—In section 6-B of the principal Act, in sub-section (1)—

(a) for the figures **"5000"**, the figures and sign **"10,000"** shall be substituted.; and

(b) in clause (e), in the first proviso, for the figures and signs **"200/-"**, the figures and signs **"400/-"** shall be substituted.

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which the Hon'ble Members of the State Legislative Assembly as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, there has been persistent demand for the revision of their existing emoluments and amenities. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Shimla :
The.....August, 2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 to 7 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 120 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C (PA) D (6)-1/2007]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2009 recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971 (ACT NO. 8 OF 1971) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section-3 Salaries and Compensatory Allowances.—(1) Subject to the condition herein contained, there shall be paid to each Member a salary at the rate of **eight thousand** rupees and compensatory allowance at the rate of five thousand per mensem with effect from the commencement of this Act or from the date on which he is declared duly elected under the Representation of the People Act, 1951 (Act No. 43 of 1951), or if such declaration is made before the vacancy occurs, from the date of occurrence of vacancy which is later.

(2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(4) Notwithstanding anything hereinbefore contained no salary and compensatory allowance shall be paid to any member in respect of any period during which he was under legal detention under any law for the time being in force.

Explanation.—The legal detention for this purpose does not include detention under any law relation to preventive detention.

4-B. Constituency secretarial and postal facilities allowance.—There shall be paid to each member a constituency, secretarial and postal facilities allowance at the rate of [1][ten thousand] rupees per mensem:]

[2][XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

4-BB. Office Allowance and Driver Allowance.—There shall be paid to each Member an office allowance mat the rate of five thousand rupees per mensem and Driver allowance at the rate of four thousand rupees per mensem.

6-AA. Compensatory constituency, secretarial postal facilities and telephone allowances and other perquisites to the exclusive of income tax.—The salary and compensatory, constituency, secretaial, postal facilities and telephone allowances payable to a Member and other perquisites admissible to him, under this Act, shall be exclusive of the income tax which shall be payable by the State Government.

Explanation.—The amount of income-tax payable by the State, would be first slab of the income assessed for income tax *i.e.* in assessing this amount, the other sources of income of the member concerned shall not be taken into consideration.

6-B Pension.—(1) There shall be paid a pension of Rs. **5000** per mensem to every person who has served for any period up to five years as,—

(*a*) a member of Assembly; or
(*b*) a member of the territorial Council; or
(*c*) partly as a member of the Assembly and partly as member of the Territorial Council; or
(*d*) a member of—
  (*i*) the Legislative Assembly of the erstwhile State of Patiala and east Punjab States Union; or
  (*ii*) the Legislative Assembly of the erstwhile Punjab State; or
  (*iii*) the Legislative Council of the erstwhile Punjab State; or
  (*iv*) partly as a member of the one and partly as a member of the other;

who has been elected or nominated to represent the whole or the part of the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab re-organisation Act, 1966.

(*e*) partly as a member of the Assembly and partly as a member of the Legislative Assembly of erswhile State of Patiala and East Punjab State Union or the Legislative Assembly/Council of the erstwhile State of Punjab, as the case may be :

Provided that where any person has served as aforesaid for a period exceeding first term, there shall be paid to him an additional pension of Rs. **200/-** per mensem for every year in excess of period of the first term, provided that for this purpose, the fraction of a year shall be counted as one year:

Provided further that while reckoning the period for the determination of the additional pension payable under the preceding proviso in the case of members elected from the constituencies comprised of Snow-bound area (non-Synchronous area) where the elections are or may be conducted on any day subsequent to the day fixed for the general elections, the period intervening the date on which the oath is administered to the members elected to the Assembly in the general elections and the date on which the oath is administered to the members elected from the Snow-bound area (non-Synchronous area) shall also be counted.

Explanation.—The expression "Snow bound area (non-Synchronous area)" means the area ccomprising Kinnaur, Lahaul and Spiti district and Pangi and Bharmour tehsil in Chamba district.

(2) Where any person entitled to pension under sub-section (1),—

(*i*) is elected to the office of the President or Vice-President or is appointed to the Office of the Governor of any State or Administrator of any Union Territory; or

(*ii*) becomes a Member of any Legislative Assembly of a State or a Union Territory or Legislative Council of State or the Metropolitan Council of Delhi constituted under section 3 of the Delhi Administration Act, 1966; or

(*iii*) is employed on a salary under the Central Government or any State Government or in a Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or local authority or becomes otherwise entitled to any remuneration from State Government, Corporations or local authority.

such person shall not be entitled to any pension under sub-section (1) for the period during which he continues to hold such office or as such member or is so employed or continues to be entitled to such remuneration:

Provided that where the salary payable to such person for holding such office or being such member or so employed or where the remuneration referred to in clause (iii) payable to such person is in either case less than the pension payable to him under sub-section (1) such person shall be entitled only to receive the balance as pension under that sub-section.

(3) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any pension, such person shall be entitled to receive the pension under sub-section (1) in addition to such other pension.

(4) In computing the number of years for the purposes of sub-section (1), the period during which a person has served as a minister, as defined in the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 or the Speaker or the Deputy Speaker of the Assembly or the Chairman of the Territorial Council shall also be taken into account.

(5) Where any person who draws pension or is entitled to draw pension, under sub-section (1), dies,—

(*i*) his/her spouse during his her life time or till he she remarries; or
(*ii*) if such person leave no spouse his minor children till they attain the age of majority and in case of daughters till they get married;

shall be entitled to draw pension at the rate of 50% of pension as admissible to such person :

Provided that where more than one person becomes entitled for pension under this sub-section all such draw the said pension in equal shares.

(5-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this where a person would have been entitled to draw pension under sub-section (1) or sub-section (1-A) of this section but for his death before the 7th day of February, 1989 he could not draw such pension, his spouse, minor children or un-married daughters shall be entitled to draw pension under sub-section (5), as if such person was alive on the 7th day of February, 1989.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where a person would have been entitled to draw pension, under sub-section (1) but for his death before the 31st day of December, 1976 he could not draw such pension—

(*i*) his/her spouse during his/her life time or till he/she remarries; or
(*ii*) if such a person leaves no spouse, his/her minor children till they attain the age of majority and in case of daughters till they get married;

shall be entitled to draw pension equal to a sum which would have been drawn by such a person as pension under this section as if such person was alive on the 31st day of December, 1976 or the sum of rupees three hundred and seventy five per mensem, whichever is higher:

Provided that the upper limit of rupees three hundred and seventy five shall not apply for the pension under this sub-section for the period from the 24th day of January, 1986 to the 31st day of March, 1988:

Provided further that where more than one person becomes entitled to pension under this sub-section, all such persons shall draw the said pension in equal shares.

(7) Every person who draws pension/family pension or is entitled to draw pension/family pension, shall in addition to the pension/family pension admissible under this section, be paid dearness relief in pension at the same rates as is admissible to other pensioners of the State Government.

ADVOCATE GENERAL, STATE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171001, *the* 14*th September*, 2009

No.3-6/80-IV-27633.—In supersession of this department notification of even number 24289- 91, dated 20th August 2009 and pursuant to her earned leave application dated 7.9.2009, ex-post facto sanction is hereby accorded to the grant of 20 days earned leave w.e.f. 17th August, 2009 to 5th September, 2009 in favour of Smt. Veena Chauhan, Superintendent of this department with permission to avail prefix/suffix Gazetted Holidays and Sundays which fell on 14th, 15th & 16th August, 2009 and 6th September, 2009.

Certified that Smt. Veena Chauhan, Superintendent would have continued to officiate, but for her proceeding on 20 days earned leave and that this period of leave will count for earning annual increment.

Certified also that said Smt. Veena Chauhan, Superintendent was likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where she proceeded on leave.

By order,
Sd/-
Advocate General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATIONS

Shimla, *the* 8*th July*, 2009

No.HHC/Admn.16 (9)74-VII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Chuni Lal and Sh. Virender Singh, Advocates, Sundernagar,

as Oath Commissioners at Sundernagar, H.P. for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

———

Shimla, the 16*th July,* 2009

No.HHC/Admn.16 (22)75-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Hukam Chand Sharma, Advocate, Sangrah as Oath Commissioner at Sangrah, H.P. for a period of two years, with effect from 17.7.2009, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

———

Shimla, the 17*th July,* 2009

No.HHC/Admn.16 (24)75-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Monika Dhiman, Sh. Anoop Kumar Kesari and Sh. Sanjiv Gupta, Advocates, Una as Oath Commissioners at Una, H.P. for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

———

Shimla, the 21*st July,* 2009

No.HHC/Admn.16 (7)74-IX.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners(Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Smt. Neetu Bloreya, Advocate, Jawali, District Kangra as Oath Commissioner at Jawali, for a period of two years, with effect from 23.8.2009 for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

———

Shimla, the 25*th July,* 2009

No.HHC/Admn.16 (34)89-I.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Mrinal, Advocate w.e.f. 7.8.2009 and Sh. Vikas Kumar, Advocate w.e.f. 10.8.2009, as Oath Commissioners at Chamba for a period of two years, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.

Shimla, the 29*th July*, 2009

No.HHC/Admn.16 (21)75-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint the following Advocates as Oath Commissioners for the High Court of Himachal Pradesh, Shimla for a period of two years from the date mentioned against their names, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules:

Sl.No.	Name of Advcate	Date of appointment
1.	Sh. Surender Thakur,	with immediate effect
2.	Sh. Varun Chandel,	with immediate effect
3.	Sh. Jai Dev,	with immediate effect
4.	Sh. Rakesh Raghuvanshi,	w.e.f. 11.8.2009
5.	Mrs. Anjna Mahindroo	w.e.f. 11.8.2009
6.	Sh. Arun Kumar	w.e.f. 11.8.2009

By order,
Sd/-
Registrar General.

ब अदालत श्री सुर्जन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती जमना देवी विधवा स्व0 श्री रेलू राम, गांव ककड़ोट, तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर–धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती जमना देवी विधवा स्व0 श्री रेलू राम ने इस अदालत मे शपथ–पत्र सहित प्रार्थना–पत्र दायर दिया है कि उसके पति स्व0 श्री रेलू राम की मृत्यु दिनांक 2–5–1992 को गांव ककड़ोट में हुई है। परन्तु ग्राम पंचायत भलवानी में मृत्यु तिथि पंजीकृत नहीं हुई है। जिसके पंजीकरण के लिए ग्राम पंचायत भलवानी को आदेश दिए जावें।

अतः इस नोटिस / इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को मृत्क श्री रेलू राम की मृत्यु तिथि के पंजीकरण बारे कोई उजर / ऐतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में दिनांक 12–10–2009 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थिया के शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थिया के पति श्री रेलू राम की मृत्यु तिथि के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत भलवानी को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07–09–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुर्जन सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Tehsildar-cum-**Executive Magistrate, Khundian, District Kangra, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Sunil Kumar s/o Budhi Singh, r/o Jujpur, Tehsil Khundian, District Kangra (H. P.)
2. Smt. Meenu Kumari d/o Shri Rattan Lal, r/o H. No. 340, Sector 12, Panchkulla, Chandigarh (Pb.)

Versus

General public

Application for the registration of marriage in the concerned Gram Panchayat.

PROCLAMATION :

Whereas Shri Sunil Kumar s/o Shri Budhi Singh, r/o Jujpur, P.O. Galoti, Tehsil Khundian, District Kangra and Smt. Meenu Kumari d/o Shri Rattan Lal, r/o H. No. 340, Sector 12, Panchkulla Chandigarh. At present w/o Shri Sunil Kumar s/o Budhi Singh, r/o Jujpur, Tehsil Khundian have filed an application alongwith an affidavit in the court that they have got married on dated 05-03-09 according to Hindu rites and customs and they are living together as a spause since then. They have not got their marriage entered in the concerned Gram Panchayat and now they want to get order to register the marriage through order.

Hence, general public is hereby informed through this notice that if any body have any objection regarding this marriage, they can file their objection inperson or through any pleader before this court on or before 20-10-2009.

After this date, no objection will be entertained and order for the registration of marriage will be passed.

Given under my hand and the seal of the court on this day of 4th Sept. 2009.

Seal. Sd/-

Tehsildar-cum-*Executive Magistrate,*
Khundian, District Kangra, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri J. R. Sharma,Tehsildar-cum-**Executive Magistrate, Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh**

Case No. ……

Shri Bhupinder Singh s/o Shri Budhi Singh, r/o Chilgari, P.O. & Teh. Dharamshala, District Kangra . . *Applicant.*

Versus

1. General Public
2. The Registrar of Marriages M. C. Dharamshala.

Subject.—Registration of Marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Public Notice.

Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 along with an affidavit stating there in that they have solemnized their marriage on 29-11-2007 at (Place) Chilgari but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages M. C. Dharamshala.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on (date) 23-10-2009 at Tehsil Office, Dharamshala at (time) 10.00 A.M. either personally of through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 9th day of Sept., 2009.

Seal.

J. R. SHARMA,
Tehsildar-cum-*Executive Magistrate,*
Dharamshala, District Kangra (H. P.).

ब अदालत श्री विनय कुमार (हि0प्र0से0), उप–मण्डल दण्डाधिकारी लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री राजन कुमार बनाम आम जनता व अन्य।

विषय.––शादी की तिथि तथा बच्चों के नाम पंचायत रजिस्टर में दर्ज करने हेतु।

श्री राजन कुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव व डाकघर गौशाल, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं सिपति, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में सशपथ प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनकी शादी 26 जुलाई, 1996 को सुनीता देवी पुत्री श्री अमर सिंह ठाकुर, गांव खंगसर के साथ हुई तथा शादी के उपरान्त पहली बच्ची गीतांजली राशपा 2 जुलाई, 1997 को तथा दूसरा बेटा आदित्य राशपा 6 अक्तूबर 2006 को पैदा हुआ है। किसी कारणवश शादी की तिथि तथा बच्चों की तारीख पैदाईश अपने पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हुई हैं, जिसे अब दर्ज किया जाना है।

अतः इस इश्तहार द्वारा समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि श्री राजन कुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव व डाकखाना गौशाल के पंचायत रजिस्टर में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 3–10–2009 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी कर सकता है तथा निश्चित तिथि पर कोई आपत्ति न करने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4–09–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। विनय कुमार,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी लाहौल स्थान केलंग
जिला लाहौल–स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत श्री नागेशवर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्रीमती गोदा देवी विधवा श्री केशव राम, निवासी ढेलू हार, डा0 डोहग, तहसील जोगिन्दरनगर
. .वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आवेदिका श्रीमती गोदा देवी विधवा श्री केशव राम, निवासी ढेलू हार ने इस अदालत में एक आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 29–12–1946 है, जोकि ग्राम पंचायत ढेलू के परिवार रजिस्टर में दर्ज न है। अब दर्ज की जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29–9–2009 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हों अन्यथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27–8–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। नागेशवर दत्त,
कार्यकारी दण्डाधिकारी जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

In the Court of Shri Vijay Kumar (HAS) Special Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh**

In the matter of :—

Pankaj Kumar aged 27 years s/o Shri Duni Chand r/o Village Sihan, P.O. Heun Pehad, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) at present dwelling in H. No. 49/5, Palace Colony Mandi Town, District Mandi, H.P. (India).

With

Abigail Singleton aged 24 years d/o Shri Stephen Clifford Singleton, r/o Flat-2, 37 West Street, Bourne, Lincowshire, PEIO 9 NB, England (bearing Passport No. PGBR 456433234) at Present c/o H. No. 49/5, Palace Colony Mandi Town, District Mandi, H. P. (India).

Versus

General public

Subject.—An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas a notice under section 15 of the Special Marriage Act has been received today on 19-08-2009 by the undersigned from Pankaj Kumar aged 27 years s/o Duni Chand r/o Village Sihan, P.O. Heun Pehad, Tehsil Sarkaghat District Mandi H.P. at present dwelling in H. No. 49/5, palace Colony Mandi Town, District Mandi H.P. (India) (Husband) and Abigail Singleton aged 24 years d/o Shri Stephen Clifford Singleton, r/o Flat-2, 37 West Street Bourne, Lincowshire, PEIO9NB, England (Passport No. PGBR 456433234) at present c/o H. No. 49/5, Palace Colony Mandi Town, District Mandi H.P. India (wife) to register their marriage under the Act *ibid.* Hence, this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 17-09-2009 at 2-00 P.M. to object registration of marriage either personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court 19th day of August, 2009.

Seal.

VIJAY KUMAR,
Special Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate Sarkaghat, District Mandi, Himachal Pradesh.*

————————

हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–4, 26 अगस्त, 2009

संख्या वि0 स0–लैज–गवरनमैंट बिल / 1–41 / 2009.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 23) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2009 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थपित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(गोवर्धन सिंह),
सचिव।

2009 का विधेयक संख्यांक 23

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2009

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.––**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2009 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 की धारा 7 में ''ग्यारह हजार और दस हजार'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''अट्ठारह हजार और सत्रह हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ठ खर्चों, जोकि मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव को जनप्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनके विद्यमान वेतन को बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1), में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मंत्री।

शिमला.....

दिनांक..... अगस्त, 2009.

———————————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित किये जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 3.60 लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

———————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

————————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[सामान्य प्रशासन विभाग नस्ति संख्या पी0ए0 (4) (डी)20 / 2007]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2009 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 2007 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख–सुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का संख्यांक 1) के उपबन्धों के उद्धरण।

7. वेतन और भत्ते.––मुख्य संसदीय सचिव प्रति मास ग्यारह हजार रुपये वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा जबकि संसदीय सचिव प्रति मास दस हजार रुपये वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, संसदीय सचिव ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते तथा अन्य परिलब्धियां प्राप्त करने का हकदार होगा जैसी सदस्यों को अनुज्ञेय हैं।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 23 of 2009

THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES (APPOINTMENT, SALARIES, ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES AND AMENITIES) AMENDMENT BILL, 2009

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 (Act No. 1 of 2007).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Amendment Act, 2009.

2. Amendment of section 7.—In section 7 of the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 for the figures and signs "11,000/-" and "10,000/-", the figures and signs "18,000/-" and "17,00/-" shall respectively be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which Hon'ble Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretary, as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase their existing salaries. This has neccessitated the amendments in the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 (Act No. 1 of 2007).

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Shimla :

The……August, 2009.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 3.60 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-PA (4) (D)-20/87]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Amendment Bill, 2009, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES (APPOINTMENT, SALARIES, ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES AND AMENITIES) AMENDMENT BILL

7. Salaries and allowances.—A Chief Parliamentary Secretary shall be entitled to the salary of **Rs. 11,000/-** per month, while a Parliamentary Secretary shall be entitled to a salary of **Rs. 10,000/-** per month. In addition, the Parliamentary Secretary shall be entitled to compensatory allowance and other perquisites as are admissible to the members.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित